सिविल, विविध

बाल राज तुली, न्यायमूर्ति

भगवान सिंह, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि–प्रतिवादी।

1971 का सिविल डब्ल्यू रिट नंबर 161।

21 जुलाई 1971.

पंजाब पुलिस नियम (1934)-नियम 12.2(3), 13.15(3) और 13.15(4)-

निरीक्षकों और उप–निरीक्षकों की वरिष्ठता की व्याख्या

पुलिस – कैसे निर्धारित – सूची 'एफ' - क्या पिछले वर्ष की सूची के प्रतिस्थापन में हर साल तैयार की जाती है – 'सूची में अधिकारियों की वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए बैच' का प्रश्न – क्या उठता है।

अभिनिर्धारित किया कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.2(3) और 13.15(4) को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक एक उप–निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक के रूप में पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक वरिष्ठता इसके अनुसार निर्धारित की जाएगी। पुलिस चयन ग्रेड के उप–निरीक्षक के रूप में उसकी पुष्टि की तिथि और यदि ऐसा कोई उप–निरीक्षक नहीं है, तो उप–निरीक्षक समयमान के रूप में। किसी व्यक्ति को इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत करने से पहले यह वरिष्ठता सब–इंस्पेक्टर के पद पर रहती है। लेकिन एक बार पुलिस निरीक्षक के रूप में उसकी पुष्टि हो जाने के बाद, पुलिस निरीक्षकों के बीच उसकी वरिष्ठता उस पद पर उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी, न कि उपनिरीक्षक रैंक के विभिन्न

अधिकारियों की पुष्टि की तारीखों के अनुसार। पुलिस का. नियम 13.15(3) के अनुसार, सूची 'एफ' को हर साल संशोधित किया जाता है, यानी, पुलिस उप महानिरीक्षकों को हर साल सूची में पहले से भर्ती अधिकारियों को बनाए रखने और हटाने के संबंध में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नए नाम जोड़ने के लिए उनकी सिफ़ारिशें। इस प्रावधान का स्पष्ट अर्थ है कि हर साल सूची की जांच करनी होगी और यह तय करना होगा कि किसे रखा जाना चाहिए, किसे हटाया जाना चाहिए और किसे जोड़ा जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की सूची के स्थान पर एक नई सूची तैयार की जाती है। इसलिए, 'बैच' का कोई सवाल ही नहीं है। हर साल सूची 'एफ' में रखे गए अधिकारियों की वरिष्ठता उन उप–निरीक्षकों की पुष्टि की तारीख के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए जिनके नाम उस सूची में हैं। जिन उप–निरीक्षकों को निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया जाता है, चाहे वे कार्यवाहक हों या वास्तविक रूप से स्थायी, नियम 13.15(3) के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट रूप से सूची 'एफ' से बाहर हो जाते हैं और निरीक्षकों के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद के वर्षों में उनके

नाम पर विचार नहीं किया जाता है। जब सूची 'एफ' को दोबारा तैयार किया जाता है।

(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरारी, मैंडामस–क्को–वारंटो या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें सरकार को सूची 'एफ' पर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता तय करने का निर्देश दिया जाए। पुलिस नियमों की सही व्याख्या के अनुसार इंस्पेक्टर और फिर उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के साथ–साथ उसे 'जी' सूची में भी लाया गया, जैसे कि न तो जांच में हस्तक्षेप किया गया था और न ही प्रत्यावर्तन के आदेश में हस्तक्षेप किया गया था। याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत करने की तारीख से प्रभावी और यह घोषणा करते हुए कि याचिकाकर्ता सभी परिणामी राहतों का हकदार है, जिसमें वरिष्ठता का

अनुदान, वेतन का बकाया आदि शामिल है और 24 दिसंबर, 1970 के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील जे.एल. गुप्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए आर.एन.मित्तल, एडवोकेट, एडवोकेट–जी जनरल, हरियाणा।

एम. एस. सिंधु, डी डिप्टी एडवोकेट–जी जनरल, पी पंजाब, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

659

भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि (तुली, न्यायमूर्ति.)

निर्णय

तुली, न्यायमूर्ति.– (1) याचिकाकर्ता, भगवान सिंह, 24 अप्रैल, 1946 को तत्कालीन कलसिया राज्य में पुलिस उप–निरीक्षक के रूप में सेवा में शामिल हुए, जिस तारीख से उन्हें उस पद पर पुष्टि की गई थी।

1948 में कलसिया राज्य सहित पूर्वी पंजाब की आठ रियासतों को एकीकृत करके पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का गठन किया गया था। सभी एकीकृत राज्यों के सेवा कर्मियों को 1 सितंबर, 1948 से संघ की सेवा में एकीकृत किया गया था, और याचिकाकर्ता को पुलिस के एक पुष्ट उप–निरीक्षक के रूप में एकीकृत किया गया था। 1952 में, वह पटियाला में सेवारत थे जहाँ श्री जनक राज पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे। याचिकाकर्ता को कर्तव्यों की घोर लापरवाही और अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण की कमी के आरोप में 5 जून, 1902 को पुलिस अधीक्षक द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जिसे पुलिस महानिरीक्षक, पेप्सू ने खारिज कर दिया – फिर उसने पेप्सू उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की जिसे 13 जुलाई, 1954 को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि याचिकाकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस अधीक्षक द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा जब वह मूल रूप से कलसिया राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। उस निर्णय के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 12 अगस्त, 1954 को उस तारीख से पुलिस उप–निरीक्षक के रूप में

बहाल कर दिया गया, जिस दिन उसे बर्खास्त किया गया था। बहाली के बाद, पुलिस महानिरीक्षक, पेप्सू द्वारा उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि 1952 में पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें सौंपे गए आरोपों पर उन्हें सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण के बाद, पुलिस महानिरीक्षक ने 9 जुलाई, 1955 से उन्हें सहायक पुलिस उप–निरीक्षक के पद पर पदावनत करने का आदेश पारित किया। उस आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने सरकार के समक्ष अपील दायर की जो तत्कालीन विलय के समय लंबित थी। पंजाब और पेप्सू राज्यों में 1 नवंबर, 1956 को हुई। उनकी अपील पर 20 जून, 1959 को निर्णय लिया गया और उनके रैंक में कटौती के आदेश को रद्द कर दिया गया, लेकिन उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि को नियम के संदर्भ में संचयी प्रभाव के बिना दो साल के लिए रोक दिया गया। पंजाब पुलिस नियम, 1934 का 16.5 (इसके बाद इसे नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा)'।

(2) अपील स्वीकार होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को उसके वेतन का बकाया नहीं दिया गया और न ही उसकी वरिष्ठता संशोधित की गई। इसलिए, उन्होंने एक सिविल मुकदमा दायर किया और रुपये की डिक्री प्राप्त की। 5 सितंबर, 1962 को वेतन के बकाया के कारण 6,262.75। याचिकाकर्ता का नाम 1962, 1963 और 1964 में सूची टी 'में लाने के लिए विचार किया गया था, लेकिन वह फिट नहीं पाया गया। हालाँकि, 1965 में, उन्हें उपयुक्त अभिनिर्धारित किया और 21 सितंबर, 1965 से सूची 'एफ' में लाया गया। 4 नवंबर, 1965 को उन्हें उस सूची से कार्यवाहक पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर, 1966 से प्रभावी हुआ, और याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया – 31 जुलाई, 1968 को पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक वरिष्ठता सूची 24 मार्च, 1969 को प्रकाशित की गई थी, जो वास्तव में प्राप्त हुई थी याचिकाकर्ता द्वारा 12 जून, 1969 को, लेकिन उन्हें उस सूची के प्रकाशित होते ही जानकारी मिल गई थी क्योंकि 4 अप्रैल, 1969 को उन्होंने उस सूची में अपने स्थान के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया था। उस सूची में,

याचिकाकर्ता की सूची 'एफ' वी में पदोन्नति की तारीख 4 नवंबर, 1964 दिखाई गई थी। जो कि 21 सितंबर, 1965 के लिए एक टाइपोग्राफिक गलती थी, जैसा कि रिटर्न में बताया गया है। उस अभ्यावेदन पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा शीघ्रता से और दिसंबर में निर्णय नहीं लिया गया। 1969, याचिकाकर्ता ने उस वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में 1969 का C.W. 3073i दायर किया। वह रिट याचिका 27 अक्टूबर, 1970 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जब इसे इस आधार पर समय से पहले खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व पुलिस महानिरीक्षक के पास निर्णय के लिए लंबित था, जिन्हें एक अवधि के भीतर इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के दो महीने बाद। उस आदेश के अनुसरण में, पुलिस महानिरीक्षक ने 19 नवंबर, 1970 को याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अपने प्रतिनिधित्व के संबंध में उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय, याचिकाकर्ता ने 1 दिसंबर, 1970 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत

किया, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक 'सी' है। याचिकाकर्ता को 22 दिसंबर, 1970 को फिर से पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। उस नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ, जिन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद और दिसंबर के एक आदेश द्वारा उसके अभ्यावेदन पर विचार किया। 24, 1970, ने उस अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत का दावा करते हुए 12 जनवरी, 1971 को वर्तमान याचिका दायर कीः –

(i) याचिका में बताए गए पुलिस नियमों की सही व्याख्या के अनुसार सूची 'एफ' पर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता तय करने के लिए सरकार को निर्देश;

(ii) सरकार को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति और उसके बाद उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश और साथ ही सूची 'जी' में लाने के लिए न तो जांच की गई और न ही आदेश 661 भगवान सिंह बनाम .हरियाणा राज्य, आदि

(तुली, न्यायमूर्ति.) ने प्रत्यावर्तन में हस्तक्षेप किया था और उस तिथि से प्रभावी था जब याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था;

(iii) उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले पुलिस महानिरीक्षक के 24 दिसंबर 1970 के आदेश को रद्द करना; और (iv) याचिकाकर्ता को वरिष्ठता, बकाया वेतन आदि सहित सभी परिणामी राहतों का हकदार घोषित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें सूची 'एफ' और उस सूची से पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था जब उनसे कनिष्ठ पहले अधिकारी को पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, उन्होंने उस अधिकारी का नाम नहीं बताया है और अपनी याचिका में केवल उत्तरदाताओं 3 और 4 को ही पक्ष बनाया है, जिसका अर्थ है कि वह चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति का दावा केवल उनके खिलाफ माना जाए।

(3) हरियाणा राज्य के साथ–साथ पंजाब राज्य द्वारा लिखित बयान दायर किए गए हैं, जिन्हें भी याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है।

662

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जोरदार ढंग से तर्क दिया गया पहला बिंदु यह है कि याचिकाकर्ता को 1952 में और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष में सूची 'एफ' में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था क्योंकि 1962 से पहले उस पदोन्नति के लिए उस पर विचार नहीं किया गया था। कारण कि उन्हें पहले सेवा से बर्खास्त किया गया और फिर उनका पद घटा दिया गया। चूंकि दोनों आदेशों को रद्द कर दिया गया था, एक 1954 में और दूसरा 1959 में। वह उन वर्षों में अपना नाम सूची 'एफ' में लाने के लिए विचार किए जाने का हकदार था, जैसे कि कोई जांच नहीं हुई थी और न ही कोई आदेश पारित किया गया था। पूर्वाग्रह। मुझे इस निवेदन से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद है। याचिका में, याचिकाकर्ता ने कहा कि पेप्सू में कोई सूची 'एफ' नहीं रखी जा रही थी, लेकिन उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा दायर रिटर्न में, यह कहा गया है कि ऐसी सूची उन नियमों के अनुसार बनाए रखी जा रही

थी जो लागू थे। वह राज्य. पुलिस उपनिरीक्षकों को सूची 'एफ' में लाने की प्रक्रिया नियमावली के नियम 13.15 में निर्धारित है। इस नियम के अनुसार, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूची 'एफ' में लाने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले पुलिस उपनिरीक्षक की सिफारिश करनी होती है। यदि पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक की सिफ़ारिश से सहमत है, तो उसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर तक अपनी सिफ़ारिश के साथ कागजात पुलिस महानिरीक्षक को अग्रेषित करना होगा। यदि वह पुलिस अधीक्षक की सिफ़ारिश से सहमत नहीं है, तो कागजात पुलिस महानिरीक्षक को नहीं भेजे जाते हैं, बल्कि उसका अपना आदेश पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाता है, जबकि पुलिस अधीक्षक की सिफ़ारिश को उस पर रखा जाता है। संबंधित उप–निरीक्षक की फ़ाइल. राज्य में पुलिस उपमहानिरीक्षकों से सिफारिशें प्राप्त होने पर, पुलिस महानिरीक्षक उनके मामलों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए विचार करते हैं और यदि वह सिफारिशों से सहमत होते हैं, तो नाम उस सूची में दर्ज किए जाते हैं। सूची 'एफ' से ही पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की जाती है। वर्ष

1952 से इस मामले को उठाने में अब बहुत देर हो चुकी है। याचिकाकर्ता को पंजाब सरकार द्वारा 1959 में उसकी अपील के निर्णय के बाद पुलिस महानिरीक्षक से यह अनुरोध करना चाहिए था, जिसमें उसे उप–निरीक्षक के रूप में बहाल किया गया था। पुलिस– उन्होंने तब ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी. वास्तव में उन्होंने 1 दिसंबर 1970 को अभ्यावेदन देने तक ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था। अपनी याचिका के साथ, याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब, चंडीगढ़ को 2 अगस्त को अपने अभ्यावेदन की एक प्रति भी दाखिल की है। 1965, प्रार्थना है कि उनका नाम बिना किसी देरी के सूची 'एफ' में लाया जाए। इस अभ्यावेदन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि उसका नाम सूची 'एफ' में लाने के मामले पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब उस पर छह महीने की अवधि के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में मुकदमा चलाया गया हो, क्योंकि 19 में उसकी बहाली के बाद। 54, वह 1961 तक पंजाब सशस्त्र पुलिस में रहे और उसके बाद उन्होंने सी.आई.डी. में सेवा की। पंजाब प्रतिनियुक्ति

पर. इस प्रकार यह महसूस किया गया कि आगे की पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए उन पर स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने कभी यह आग्रह नहीं किया कि वह पिछले वर्षों में सूची 'एफ' में अपना नाम आने पर विचार किए जाने का हकदार है। पुलिस अधीक्षक को फॉर्म 13.15 (1) में एक सिफारिश करनी होती है जिसमें एक कॉलम है – "क्या वह अच्छे और मजबूत चरित्र का आदमी है जो अनुशासन लागू कर सकता है" और एक अन्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना है – "क्या उसके पास है" आम तौर पर आपका विश्वास ” ऊपर जो कहा गया है, उसके अनुसार, 1952 में याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों में लापरवाह और अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण की कमी वाला पाया गया। जाहिर है, इस आरोप के मद्देनजर उनके मामले को पुलिस अधीक्षक द्वारा सूची 'एफ' में शामिल करने के लिए दोबारा अनुशंसित नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि जब 1959 में अंततः सरकार द्वारा उनकी अपील स्वीकार कर ली गई, तब भी उन्हें आरोप से पूरी तरह बरी नहीं

किया गया; केवल सज़ा कम की गई। यह याद रखना होगा कि उन्हें इसी आरोप में 1955 में दंडित किया गया था और इसलिए, यह अनुमान लगाना वैध है कि उनके नाम को 1959 तक सूची 'एफ' में शामिल करने के लिए अनुशंसित नहीं किया गया होगा। इसके बाद, उनके नाम पर चार बार विचार किया गया। 1962, 1963 और 1964, लेकिन उन्हें फिट नहीं पाया गया। अंततः, 1965 में उन्हें योग्य अभिनिर्धारित किया और उनका नाम 'एफ' सूची में लाया गया और उन्हें 4 नवंबर, 1965 से कार्यवाहक निरीक्षक के रूप में आगे पदोन्नति दी गई – इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं ऐसा नहीं मानता 1952 के बाद से सूची 'एफ' में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर विचार करने के लिए प्रतिवादी 1 को निर्देश देने से उपयोगी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसलिए, इस बिंदु पर विद्वान वकील द्वारा किया गया निवेदन निरस्त किया जाता है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया दूसरा बिंदु सूची 'एफ' में याचिकाकर्ता को आवंटित वरिष्ठता के संबंध में है।

रिटर्न के अनुसार, याचिकाकर्ता को तिथि के अनुसार अपने बैच में उचित वरिष्ठता आवंटित की गई है। उपनिरीक्षक के रूप में उनकी पुष्टि की। रिटर्न से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि 'बैच' का मतलब क्या है। यदि इसका मतलब उन उप-निरीक्षकों से है जिन्हें 21 सितंबर, 1965 को उस सूची में पहले से ही उप-निरीक्षकों पर विचार किए बिना सूची 'एफ' में जोड़ा गया था, तो, मेरी राय में, वरिष्ठता सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी। निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने से पहले सूची 'एफ' पर अधिकारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में प्रासंगिक प्रावधान नियम 12.2(3) और नियम 13.15 (4) में निहित हैं जो निम्नानुसार हैं: - "12.2'(3). नामांकित पुलिस अधिकारियों की सभी नियुक्तियाँ प्रत्येक रैंक पर लागू इस अध्याय के नियमों के अनुसार परिवीक्षा पर हैं। ऊपरी अधीनस्थों के मामले में वरिष्ठता की गणना प्रथम दृष्टया पहली नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, निचले पद से पदोन्नत अधिकारियों को उसी तिथि पर सीधे नियुक्त किए गए

व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जाएगा, और उसी पर सीधे नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता आयु के अनुसार तिथि की गणना की जा रही है। हालाँकि, वरिष्ठता अंततः पुष्टि की तारीखों से तय की जाएगी, कई अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता उसी तारीख को पुष्टि की जाएगी जो उन्हें पहली नियुक्ति पर आवंटित की गई थी। बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जिसकी पदोन्नति या पुष्टिकरण उसकी सीमा या जिले के बाहर प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण विलंबित हो, पदोन्नत या पुष्टि होने पर, वह वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो उसने मूल रूप से अपने से पहले पदोन्नत या पुष्टि किए गए अधिकारियों की तुलना में धारण की थी। अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान. निचले अधीनस्थों की वरिष्ठता की गणना नियम 12.24 की शर्तों के अधीन नियुक्ति की तारीखों से की जाएगी और बशर्ते कि एक पदोन्नत अधिकारी उसी तारीख को उसी रैंक पर सीधे नियुक्त अधिकारी से वरिष्ठ होगा। 664 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1973)2 “13.15(4) सूची 'एफ' में भर्ती किए

गए उप–निरीक्षक को चयन ग्रेड में स्थायी पदोन्नति की तारीख के अनुसार उस सूची में रखा जाएगा और, यदि चयन ग्रेड में स्थायी पदोन्नति की तारीख समान है दो या दो से अधिक उप–निरीक्षकों के मामले को एक ही तिथि पर 'एफ' सूची में भर्ती किया गया, तो समय–मान में स्थायी पदोन्नति की तिथि के अनुसार। सार्जेंटों को सूची में प्रवेश की तिथि के अनुसार सूची 'एफ' में दिखाया जाएगा– हालाँकि, जब दो या दो से अधिक सार्जेंटों को एक ही तिथि पर सूची 'एफ' में प्रवेश दिया जाता है, तो उनके नाम आपस में वरिष्ठता के क्रम में दिखाए जाएंगे। /'

इन दोनों नियमों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक एक उप–निरीक्षक को पुलिस निरीक्षक के रूप में पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक वरिष्ठता पुलिस चयन ग्रेड के उप–निरीक्षक के रूप में उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार निर्धारित की

जाएगी और यदि कोई नहीं है ऐसे सब–इंस्पेक्टर, फिर सब–इंस्पेक्टर टाइम–स्केल के रूप में। किसी व्यक्ति को इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत करने से पहले यह वरिष्ठता सब–इंस्पेक्टर के पद पर रहती है। लेकिनः एक बार पुलिस निरीक्षक के रूप में उसकी पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस निरीक्षकों के बीच उसकी वरिष्ठता उस पद पर उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी, न कि उप रैंक के विभिन्न अधिकारियों की पुष्टि की तारीखों के अनुसार। –पुलिस निरीक्षक. नियम 13.15(3) के अनुसार, सूची 'एफ' को हर साल संशोधित किया जाता है, यानी, पुलिस उप महानिरीक्षकों को हर साल सूची में पहले से भर्ती अधिकारियों को बनाए रखने और हटाने के संबंध में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नए नाम जोड़ने के लिए उनकी सिफ़ारिशें। इस प्रावधान का स्पष्ट अर्थ है कि हर साल सूची की जांच करनी होगी और यह तय करना होगा कि किसे रखा जाना चाहिए, किसे हटाया जाना चाहिए और किसे जोड़ा जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की सूची के स्थान पर एक नई सूची तैयार

की जाती है। इसलिए, 'बैच' का कोई सवाल ही नहीं है। हर साल सूची 'एफ' में रखे गए अधिकारियों की वरिष्ठता उन उपनिरीक्षकों की पुष्टि की तारीख के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए जिनके नाम उस सूची में हैं। जिन उप–निरीक्षकों को निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया जाता है, चाहे वे कार्यवाहक हों या स्थायी रूप से, नियम 13.15(3) के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट रूप से आईटी 'एफ' से बाहर चले जाते हैं और उनके नाम पर उनकी पदोन्नति के बाद के वर्षों में विचार नहीं किया जाता है। इंस्पेक्टर के रूप में जब सूची 'एफ' को दोबारा तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, याचिकाकर्ता ने इस याचिका में केवल प्रतिवादी 3 और 4 की पदोन्नति को चुनौती दी है, किसी अन्य अधिकारी की नहीं। इन उत्तरदाताओं के संबंध में विवरण यह है कि प्रतिवादी 3 को 4 मार्च, 1961 को सूची 'एफ' में लाया गया था, 19 मई, 1961 को निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, और 1 दिसंबर, 1967 को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि प्रतिवादी 4 को 11 जून 1962 को सूची 'एफ' में लाया गया। 5 नवंबर 1962 को निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया, और 1 जनवरी 1968 को पुलिस

उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। जब याचिकाकर्ता का नाम 21 सितंबर, 1965 को सूची 'एफ' में लाया गया, तो जाहिर तौर पर ये दोनों उत्तरदाता पुलिस निरीक्षक के रूप में अपनी पदोन्नति के कारण उस सूची से बाहर हो गए थे और सूची 'एफ' में याचिकाकर्ता की वरिष्ठता तय नहीं की जा सकी थी। इन उत्तरदाताओं के सामने। इसलिए, याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और वह किसी राहत का हकदार नहीं है।

665

(6) याचिकाकर्ता के पास 12 जून 1969 से वरिष्ठता सूची है, लेकिन उसने रिट याचिका में उन पुलिस उप–निरीक्षकों के नामों का उल्लेख नहीं किया है जो 21 सितंबर 1965 को सूची 'एफ' में थे। , जब उनका नाम उस सूची में लाया गया था और उनकी वरिष्ठता गलत तरीके से तय की गई थी। इसके अलावा, सूची 'एफ' पर वरिष्ठता का अब कोई महत्व नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है। सूची 'जी' और पुलिस उपाधीक्षक के पद पर उनकी आगे की पदोन्नति पुलिस निरीक्षक के पद पर उनके प्रदर्शन पर

निर्भर करेगी, न कि सूची 'एफ' में उनकी वरिष्ठता पर। इसलिए, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत देना संभव नहीं है।

(7) ऊपर दिए गए कारणों से, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है जिसे खारिज कर दिया गया है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा